भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4268
19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

समुद्री शैवाल की खेती

4268. श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में समुद्री शैवाल की खेती की मात्रा का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) आंध्र प्रदेश में समुद्री शैवाल की खेती वाले स्थानों की सूची का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययनों के अनुसार अपतटीय और तटीय समुद्री शैवाल की खेती के लिए चिन्हित स्थानों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने समुद्री शैवाल की खेती की उपज और उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का कोई आकलन किया है;
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा समुद्री शैवाल की जलवायु- सह्य किस्मों को विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ग): अनुकूल परिस्थितियों वाले 11,099 किलोमीटर लंबे भारतीय समुद्री तट में समुद्री शैवाल (सी वीड़) की खेती की अपार संभावनाएं हैं। ICAR-सेन्ट्रल मरीन फिशरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFR) के अनुसार, भारत में सालाना लगभग 9.7 मिलियन टन सी वीड़ उत्पादन क्षमता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार एक प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को कार्यान्वित कर रहा है और सी वीड़ कल्टीवेशन PMMSY के तहत पहचानी गई प्राथमिकता वाली गतिविधियों में से एक है, जिसका उद्देश्य मछुआरों और तटीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन और आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना है। तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही PMMSY में अन्य बातों के साथ-साथ सी वीड़ कल्टीवेशन और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है। PMMSY के तहत विगत 5 वर्षों (2020-25) के दौरान 195 करोड़ रु/- की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें तमिलनाडु में एक सी वीड़ पार्क (127.71 करोड़ रु/-) की स्थापना भी शामिल है। इसके अलावा, PMMSY के तहत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सी वीड़ कल्चर यूनिट्स (राफ्ट, मोनोलाइन/ट्यूबनेट सिस्टम) की स्थापना, सी वीड़ सीड बैंकों की स्थापना, पोस्ट हारवेस्ट की सुविधाएं जैसे सुखाने वाले प्लेटफार्म, बेलिंग यूनिट और स्टोरोज गोदाम, जल परीक्षण और जर्मप्लाज्म क्वारंटाइन के लिए प्रयोगशालाएं, और इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ प्रशिक्षण परिसर, पूर्व-व्यवहार्यता मूल्यांकन अध्ययन, जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, लक्षद्वीप को सीवीड क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है, और ICAR-CMFRI के मंडपम क्षेत्रीय केंद्र को सीवीड फार्मिंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है । मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार द्वारा सी वीड़ जर्मप्लाज्म के आयात हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने देश में इस आशाजनक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक सी वीड़ पॉलिसी रिपोर्ट भी जारी की है। देश में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार द्वारा सी वीड़ विकास पर इंटर-मिनिस्टीरियल कमिटी (IMC) और टेक्निकल ऐडवाईसरी कमिटी (TAC) के रूप में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। सी वीड़ कल्टीवेशन मुख्यतः तमिलनाडु, गुजरात और लक्षद्वीप में होती है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पायलट परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। इन पहलों के परिणामस्वरूप, सी वीड़ का उत्पादन 2015 में 18,890 टन से बढ़कर 2024 में 74,083 टन हो गया है।

अनुसंधान संस्थानों ने भारत के तटीय क्षेत्र में 24,707 हेक्टेयर क्षेत्र में सी वीड़ कल्टीवेशन के लिए 384 उपयुक्त स्थलों की पहचान की है, जिनमें आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में 40 स्थल (1355 हेक्टेयर) शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में सी वीड़ क्षेत्र अभी भी प्रायोगिक चरण में है, और सी वीड़ कल्टीवेशन के प्रायोगिक अध्ययन निम्नलिखित 4 स्थानों पर चल रहे हैं:

क्रम सं.	**ज़िला**	**मंडल**	**स्थान**
1	श्रीकाकुलम	एचेरला	बुदागटलापलेम
2	विशाखापत्तनम	भीमिली	आरके बीच
3	बापतला	चिनगंजम	येतिमोगा
4	SPSR नेल्लोर	उलवापाडु	रामायपट्टनम

(घ) से (च): ICAR-CMFRI ने सूचित किया है कि सी वीड़ की विभिन्न प्रजातियों जैसे कप्पाफाइकस और ग्रेसिलेरिया की खेती की तकनीक और उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं । चूंकि आंध्र प्रदेश में सी वीड़ क्षेत्र अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार टिशू/स्पोर कल्चर के माध्यम से उन्नत कल्टीवेशन तकनीकों को बढ़ावा दे रही है, मल्टी स्पीशीस सीड बैंकों की स्थापना कर रही है, गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म के आयात की सुविधा प्रदान कर रही है, और ICAR-CMFRI सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, CSIR-CSMCRI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसेन टेक्नॉलाजी (NIOT) और नेशनल सेन्टर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मेनेजमेंट (NCSCM) आदि के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अक्टूबर, 2024 में 'गाइडलाइन फॉर इम्पोर्ट ऑफ लाइव सी वीड़ इन्टू इंडिया' जारी किए हैं ताकि विदेशों से उच्च गुणवत्ता वाले सीड़ सामग्री या जर्मप्लाज्म के आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिससे किसानों को गुणवत्ता वाले सीड़ स्टॉक तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डोमेस्टिक मल्टीप्लीकेशन को सक्षम किया जा सके।

***